



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार 14 मार्च, 2013/23 फाल्गुन, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला, 13 मार्च, 2013

संख्या वि.स.-विधायन-अनु. बजट/1-26-2013.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हि0 प्र0 विनियोग विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 1) जो आज दिनांक 13 मार्च, 2013 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित/-

सचिव,

हि0 प्र0 विधान सभा ।

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2013

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, हिमाचल प्रदेश राज्य की सचि त निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय और धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम.**— इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2013 है ।
2. **हिमाचल प्रदेश राज्य की सचि त निधि में से वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए 8,70,16,39,392 रुपए की और राशि जारी करना.**— हिमाचल प्रदेश राज्य की सचि त निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक धनराशियों जिनका योग 8,70,16,39,392 रुपए (आठ सौ सतर करोड़ सोलह लाख उनतालीस हजार तीन सौ बानवे रुपए) हैं, संदत्त और उपयोजित की जाए, जिनका वित्तीय वर्ष 2012-2013 की अवधि में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों से सम्बन्धित विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा।
3. **विनियोग.**— इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की सचि त निधि में से संदत्त और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत धनराशियों का इस अधिनियम की धारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और विनियोजन किया जाएगा।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

मांग संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा दत्तमत ₹	सचि त निधि पर प्रभारित ₹	जोड़ ₹
1	2	3	4	5
1	विधान सभा (राजस्व) (पूंजी)	1,10,65,000 3,03,31,000	— —	1,10,65,000 3,03,31,000
2	राज्यपाल और मन्त्री परिषद् (राजस्व)	75,59,000	91,000	76,50,000
3	न्याय प्रशासन (राजस्व) (पूंजी)	1,71,64,000 3,79,10,000	1,58,60,000 —	3,30,24,000 3,79,10,000
4	सामान्य प्रशासन (राजस्व) (पूंजी)	4,98,88,000 2,86,50,000	84,49,000 —	5,83,37,000 2,86,50,000
5	भू-राजस्व और जिला प्रशासन (राजस्व) (पूंजी)	67,82,68,678 40,00,000	— —	67,82,68,678 40,00,000

1	2	3	4	5
6	आबकारी और कराधान (राजस्व) (पूँजी)	12,87,18,000 4,50,00,000	— —	12,87,18,000 4,50,00,000
7	पुलिस और सम्बद्ध संगठन (राजस्व) (पूँजी)	32,18,41,098 2,17,17,000	25,40,649 —	32,43,81,747 2,17,17,000
8	शिक्षा (राजस्व)	75,83,48,100	43,47,280	76,26,95,380
9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजस्व)	21,14,39,000	—	21,14,39,000
10	लोक निर्माण - सड़क, पुल तथा भवन (राजस्व) (पूँजी)	1,000 8,24,17,000	— 4,02,97,000	1,000 12,27,14,000
11	कृषि (राजस्व)	31,23,32,430	—	31,23,32,430
12	उद्यान (पूँजी)	12,49,99,000	—	12,49,99,000
13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई (राजस्व) (पूँजी)	— 3,000	2,51,870 —	2,51,870 3,000
14	पशु पालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य (राजस्व) (पूँजी)	5,000 4,53,35,500	914 —	5,914 4,53,35,500
15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना (राजस्व) (पूँजी)	37,18,000 52,60,50,000	— —	37,18,000 52,60,50,000
16	वन और वन्य जीवन (राजस्व) (पूँजी)	2,000 26,36,000	2,83,260 —	2,85,260 26,36,000
17	निर्वाचन (राजस्व)	18,16,32,529	—	18,16,32,529
18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति और सूचना एवं प्रौद्योगिकी (राजस्व) (पूँजी)	6,58,68,659 4,80,00,000	— —	6,58,68,659 4,80,00,000
19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (राजस्व) (पूँजी)	43,27,24,549 5,00,000	— —	43,27,24,549 5,00,000
20	ग्रामीण विकास (राजस्व)	28,09,99,000	—	28,09,99,000
21	सहकारिता (राजस्व) (पूँजी)	42,65,000 85,14,000	— —	42,65,000 85,14,000
22	खाद्य और नागरिक आपूर्ति (राजस्व)	19,59,93,345	2,06,953	19,62,00,298
23	विद्युत विकास (राजस्व)	73,79,60,054	—	73,79,60,054
24	मुद्रण और लेखन सामग्री (राजस्व)	13,59,000	—	13,59,000
25	सड़क और जल परिवहन (राजस्व) (पूँजी)	73,41,76,000 5,77,000	— —	73,41,76,000 5,77,000

1	2	3	4	5
27	श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण (राजस्व) (पूँजी)	9,39,81,932 18,43,77,000	— —	9,39,81,932 18,43,77,000
28	शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	54,92,25,000	—	54,92,25,000
29	वित्त (राजस्व) (पूँजी)	12,000 1,000	47,23,68,327 —	47,23,80,327 1,000
30	विविध सामान्य सेवाएं (राजस्व)	8,21,34,103	—	8,21,34,103
31	जनजातीय विकास (राजस्व) (पूँजी)	28,70,46,400 10,03,000	18,962 —	28,70,65,362 10,03,000
32	अनुसूचित जाति उप-योजना (राजस्व) (पूँजी)	62,60,46,800 19,11,30,000	— —	62,60,46,800 19,11,30,000
	(राजस्व)	6,77,37,73,677	50,44,18,215	7,27,81,91,892
	(पूँजीगत)	1,38,31,50,500	4,02,97,000	1,42,34,47,500
	कुल जोड़	8,15,69,24,177	54,47,15,215	8,70,16,39,392

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के साथ पठित अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की सचि त निधि में से वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमानित व्ययों के सम्बन्ध में सचि त निधि पर प्रभारित व्ययों और विधान सभा द्वारा यथा दत्तमत अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए, हिमाचल प्रदेश राज्य की सचि त निधि में से अपेक्षित और धन के विनियोजन का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है ।

(वीरभद्र सिंह)
मुख्य मन्त्री ।

शिमला :

तारीख 13 मार्च, 2013

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(वित्त विभाग नस्ति संख्या: फिन-ए-सी (6)-2/2012)

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2013 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं ।

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION BILL, 2013

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A**BILL**

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year ending on the 31st day of March, 2013.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixtys-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation Act, 2013.

2. Issue of a further sum of ₹ 8,70,16,39,392 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2012-2013.—From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of ₹ 8,70,16,39,392 (Rupees Eight hundred seventy crores sixteen lakh thirty nine thousand three hundred ninety two only) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 2012-2013 in respect of the services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

3. Appropriation.—The sums authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be further appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the period specified under section 2 of this Act.

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

Demand No.	Services and purposes	Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
		₹	₹	₹
1	2	3	4	5
1	Vidhan Sabha (Revenue)	1,10,65,000	—	1,10,65,000
	(Capital)	3,03,31,000	—	3,03,31,000
2	Governor and Council of Ministers (Revenue)	75,59,000	91,000	76,50,000
3	Administration of Justice (Revenue)	1,71,64,000	1,58,60,000	3,30,24,000
	(Capital)	3,79,10,000	—	3,79,10,000

1	2	3	4	5
4	General Administration (Revenue) (Capital)	4,98,88,000 2,86,50,000	84,49,000 —	5,83,37,000 2,86,50,000
5	Land Revenue and District Administration (Revenue) (Capital)	67,82,68,678 40,00,000	— —	67,82,68,678 40,00,000
6	Excise and Taxation (Revenue) (Capital)	12,87,18,000 4,50,00,000	— —	12,87,18,000 4,50,00,000
7	Police and Allied Organisations (Revenue) (Capital)	32,18,41,098 2,17,17,000	25,40,649 —	32,43,81,747 2,17,17,000
8	Education (Revenue)	75,83,48,100	43,47,280	76,26,95,380
9	Health and Family Welfare (Revenue)	21,14,39,000	—	21,14,39,000
10	Public Works—Roads, Bridges and Buildings (Revenue) (Capital)	1,000 8,24,17,000	— 4,02,97,000	1,000 12,27,14,000
11	Agriculture (Revenue)	31,23,32,430	—	31,23,32,430
12	Horticulture (Capital)	12,49,99,000	—	12,49,99,000
13	Irrigation, Water Supply and Sanitation (Revenue) (Capital)	— 3,000	2,51,870 —	2,51,870 3,000
14	Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries (Revenue) (Capital)	5,000 4,53,35,500	914 —	5,914 4,53,35,500
15	Planning and Backward Area Sub-Plan (Revenue) (Capital)	37,18,000 52,60,50,000	— —	37,18,000 52,60,50,000
16	Forest and Wild Life (Revenue) (Capital)	2,000 26,36,000	2,83,260 —	2,85,260 26,36,000
17	Election (Revenue)	18,16,32,529	—	18,16,32,529
18	Industries, Minerals, Supplies & Information Technology (Revenue) (Capital)	6,58,68,659 4,80,00,000	— —	6,58,68,659 4,80,00,000
19	Social Justice and Empowerment (Revenue) (Capital)	43,27,24,549 5,00,000	— —	43,27,24,549 5,00,000
20	Rural Development (Revenue)	28,09,99,000	—	28,09,99,000
21	Co-operation (Revenue) (Capital)	42,65,000 85,14,000	— —	42,65,000 85,14,000
22	Food and Civil Supplies (Revenue)	19,59,93,345	2,06,953	19,62,00,298
23	Power Development (Revenue)	73,79,60,054	—	73,79,60,054

1	2	3	4	5
24	Printing and Stationery (Revenue)	13,59,000	—	13,59,000
25	Road and Water (Revenue) Transport (Capital)	73,41,76,000 5,77,000	— —	73,41,76,000 5,77,000
27	Labour, Employment (Revenue) and Training (Capital)	9,39,81,932 18,43,77,000	— —	9,39,81,932 18,43,77,000
28	Urban Development, (Revenue) Town and Country Planning and Housing	54,92,25,000	—	54,92,25,000
29	Finance (Revenue) (Capital)	12,000 1,000	47,23,68,327 —	47,23,80,327 1,000
30	Miscellaneous General (Revenue) Services	8,21,34,103	—	8,21,34,103
31	Tribal Development (Revenue) (Capital)	28,70,46,400 10,03,000	18,962 —	28,70,65,362 10,03,000
32	Scheduled Castes Sub- (Revenue) Plan (Capital)	62,60,46,800 19,11,30,000	— —	62,60,46,800 19,11,30,000
	Total (Revenue)	6,77,37,73,677	50,44,18,215	7,27,81,91,892
	(Capital)	1,38,31,50,500	4,02,97,000	1,42,34,47,500
	Grand Total	8,15,69,24,177	54,47,15,215	8,70,16,39,392

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of article 204 read with article 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys further required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly in respect of the estimated expenditure of the Government of Himachal Pradesh for the financial year 2012-2013.

(VIR BHADRA SINGH)
Chief Minister.

SHIMLA :
The 13th March, 2013.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Finance Department File No. Fin-A-C (6)-2/2012]

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of Himachal Pradesh Appropriation Bill, 2013, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction in and consideration by the Legislative Assembly of the said Bill.

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 फरवरी, 2013

संख्या: आई.पी.एच.-ए.-बी (1)-15/2011.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में सर्वेक्षक, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-“क” के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, सर्वेक्षक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.**—(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या: आई.पी.एच.-ए.-ए. (3)-33/96, तारीख 21.12.1996 द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, वर्क चार्ज्ड सर्वेयर (सर्वेक्षक) वर्ग-III (अराजपत्रित) पद, भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 1996 का उस विस्तार तक एतद्वारा निरसन किया जाता है जहां तक ये नियमित (सर्वेक्षक) वर्ग-III (अराजपत्रित) पर लागू हुए वर्क चार्ज्ड पद से संबंधित हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

उपाबन्ध- “क”

हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में सर्वेक्षक, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**— सर्वेक्षक

2. **पदों की संख्या.**— 321 (तीन सौ इक्कीस)

3. **वर्गीकरण.**— वर्ग-III (अराजपत्रित) राज्य काडर।

4. **वेतनमान.**—(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान.—पे बैंड 5910—20200 रुपए 2400/—रुपए ग्रेड पे।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.—स्तम्भ 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 8310/— रुपए प्रतिमास।

5. **चयन पद अथवा अचयन पद.**— अचयन।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.— 18 से 45 वर्ष:

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदर्शों) के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेसन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्पूर्वी ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.—(क) अनिवार्य अर्हताएं.— (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से 10+2 परीक्षा पास की हो ।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या हिमाचल प्रदेश/केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्वेक्षण कार्य के ट्रेड में सर्टिफिकेट या इसके समतुल्य ।

(ख) **वॉछनीय अर्हता.**—हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं.—आयु.— लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हता.— लागू नहीं ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.— दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे ।

10. भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी नियमित या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.— शतप्रतिशत शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा ।

11. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना.—लागू नहीं ।
12. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
13. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएँ.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।
14. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
- 15—क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद नियुक्ति के लिए चयन.—पर इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियाँ, नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएंगी:—
- (I) संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में सर्वेक्षक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा:
- परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि विस्तारित/नवीकृत किया जाएगा ।
- (ख) पद का हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.—सम्बद्ध अधीक्षण अभियन्ता रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।
- (ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।
- (II) संविदात्मक उपलब्धियाँ.—संविदा के आधार पर नियुक्त सर्वेक्षक को 8310/—रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 249/— रूपए की रकम (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।
- (III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.—सम्बद्ध वृत्त का अधीक्षण अभियन्ता, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।
- (IV) चयन प्रक्रिया.—संविदा नियुक्तियों की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
- (V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

(VI) करार.—अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध—“ख” के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 8310/— रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 249/—रूपए की रकम (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए भी हकदार/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश, एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य(ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक ही स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0—एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षण.— सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय—समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.— लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.— जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध— “ख”

सर्वेक्षक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग,
हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति..... पुत्र/पुत्री श्री.....
निवासी....., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् “प्रथम पक्षकार” कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् “द्वितीय पक्षकार” कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया।

“द्वितीय पक्षकार” ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने सर्वेक्षक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार सर्वेक्षक के रूप में, से प्रारम्भ होने और..... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्.....दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 8310/— रूपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त सर्वेक्षक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए भी हकदार होगी। वह, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त सर्वेक्षक को उपरोक्त के सिवाय किसी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त सर्वेक्षक कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
6. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहाँ भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा:

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में :

1.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

.....

नाम व पूरा पता

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English text of this Department Notification No. IPH A-B(1)-15/2011 dated 20-2-2013, as required under Clause (3) of Article 348.]

IRRIGATION AND PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 20th February, 2013

No. IPH A-B(1)-15/2011.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Surveyor Class-III (Non-Gazetted) in Irrigation and Public Health Department, H.P. as per Annexure-‘A’ appended to this notification, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called Himachal Pradesh Department of Irrigation & Public Health, Surveyor Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2013.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal & Savings.—(1) The Himachal Pradesh Irrigation & Public Health Department Surveyor Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules notified vide this department notification No. IPH A-A (3)-33/96 dated 21-12-1996 and as amended from time to time are hereby repealed to the extent these pertains to the post Work Charged brought on Regular Surveyor (Class-III Non-Gazetted).

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any action taken or any thing done under the rules so repealed under Rule-2 (1) supra shall be deemed to have been validly made or taken under these rules.

By order,
Sd/-
Principal Secretary (IPH).

ANNEXURE-“A”

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SURVEYOR (NON GAZETTED) CLASS-III, IN THE DEPARTMENT OF IRRIGATION & PUBLIC HEALTH, HIMACHAL PRADESH.

- 1. Name of the post.**—Surveyor.
- 2. Number of post(s).**—321 (Three hundred and twenty one).
- 3. Classification.**—Class-III (Non-Gazetted) State Cadre.
- 4. Scale of pay.**— *i) Pay Scale of regular incumbents :*
Pay Band ₹ 5910-20200+ ₹2400/- Grade Pay.
ii) Emoluments for contract employees :
₹ 8,310 as per details given in Column 15-A.
- 5. Whether “Selection” post or “Non- Selection” post.**—Not applicable.
- 6. Age for direct recruitment.**—Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become overage on the date when he/she was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes / Schedule Tribes / Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector corporations / Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations / Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations / Autonomous Bodies who were / are subsequently appointed by such Corporation / Autonomous Bodies and who are /were finally absorbed in the service of such Corporations / Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations / Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post (s) is / are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment relax able at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational & other qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualification(s): i) Should have passed 10+2 examination from a recognized Board / University.

ii) Certificate in the trade of Survey Work or its equivalent from a recognized I.T.I. or from an institute duly recognized by the Central / H.P. Government.

(b) Desirable Qualification(s): Knowledge of customs, manners and Dialects of Himachal Pradesh and Suitability for appointment in the peculiar condition prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and Educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).—Age : Not applicable.

Educational Qualification : Not applicable.

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment, whether by recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?—Not applicable.

12. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

13. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

14. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of vivavoce test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard /syllabus etc. of which will be determined by the Commission/ other recruiting authority, as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Surveyor in Department of Irrigation & Public Health, HP will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB:

The Superintending Engineers concerned after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Surveyor appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹ 8310/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of ₹ 249/- (3% of the minimum of pay band plus grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/ DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Superintending Engineer of the concerned Circle H.P. will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-“B” appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ₹ 8310/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ₹ 249/- (3% of the minimum of pay band plus grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as seniority scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 day's Medical Leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbusement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duties without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Govt. / Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer / Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Backward Classes / Other Backward Classes/ other Categories of persons issued by the H.P. Govt. from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the HPPSC relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

ANNEXURE-“B”

Form of contract/agreement to be executed between the Surveyor & the Government of Himachal Pradesh through Superintending Engineer, Irrigation & Public Health Department

This agreement is made on this day of in the year..... between Sh/Smt.S/o/D/o Shri.....R/o.....

Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Superintending Engineers IPH Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Surveyor on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Surveyor for a period of one year commencing on day of It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on And information notice shall not be necessary.
2. The contract amount of the FIRST PARTY will be ₹ 8310/- P.M.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual Surveyor will be entitled for one day's casual leave after putting in one-month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 day's Medical Leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contractual Surveyor.

Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Surveyor will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ practitioner.
8. Contractual appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part Officer at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee (s).

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOO shall issue a certificate that the services and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period old contract is to be renewed /extended.

IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WISTNESS:

1. _____

(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. _____

(Name & Full Address)

IN THE PRESENCE OF WSITNESS:

1. _____

(Name & Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2. _____

(Name & Full Address)

आबकारी व कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2 13 मार्च, 2013

संख्या-ई0एक्स0एन0-एफ(1)2/2012.—प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट राज्य क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब एक्साइज ऐक्ट, 1914 (1914 का 1) की धारा 58 की उपधारा (2) के खण्ड (f) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उन्हें निहित समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, समय-समय पर यथा संशोधित विभाग की अधिसूचना संख्या:1-17/84-ई0एण्ड टी0, तारीख 02-09-1965 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश इन्टॉक्सिकैन्टस लाइसेंस एण्ड सले ऑर्डरज़, 1965 में, तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करने के आदेश देती है :-

संशोधन

उक्त ऑर्डरज़ में: —

उक्त ऑर्डरज़ के ऑर्डर 4 के पश्चात निम्नलिखित नया प्रोवाइजो अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

After order 4 of the said order, new proviso shall be inserted by the following, namely:—

“Provided that the Financial Commissioner (Excise) may open new liquor vends in an area where 3 FIR’s of illicit distillation, illegal sale etc. are lodged by the Police.”

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/—

प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) ।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. EXN-F(1)-2/2012, dated 13-03-2013 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 13rd March, 2013

No. EXN- F(1)-2/2012.—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of Section 58 of the Punjab Excise Act, 1914 (1 of 1914) as in force in the territories comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and all other powers enabling her in this behalf, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to order the following amendment in the Himachal Pradesh Intoxicants License and Sale Orders, 1965, notified vide Department Notification No.1-17/84-E&T, dated 2.9.1965 as amended from time to time with immediate effect:—

AMENDMENT

In the said orders:—

After order 4 of the said order, new proviso shall be inserted by the following, namely:—

“Provided that the Financial Commissioner (Excise) may open new liquor vendis in an area where 3 FIR's of illicit distillation, illegal sale etc. are lodged by the Police.”

By order,
Sd/-
Principal Secretary (E&T).

आबकारी व कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला—2 13 मार्च, 2013

संख्या—ई0एक्स0एन0—एफ(1)2/2012(i).—प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट राज्य क्षेत्रों को यथा लागू ईस्ट पंजाब मेलैसिज़ (कन्ट्रोल) ऐक्ट, 1948 की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, ईस्ट पंजाब मेलैसिज़ (कन्ट्रोल) (हिमाचल प्रदेश) रुलज़, 1973 में तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

उक्त रुलज़ में:—

उक्त रुलज़ के रुलज़ 14 के सब रुल (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

Sub-rule(2) of Rule 14 of the said rules shall be substituted by the following, namely :—

“Every Distillers or manufacturers of Cattle Feed and Briquettes etc. shall furnish to the AETC/ETO I/C of the District concerned a monthly return in Form M.C.7 given below with

copies thereof to the Collector (Excise) of the Zone concerned and the Excise & Taxation Commissioner, Himachal Pradesh, showing the receipt and consumption of molasses and quantity of Spirit/Cattle Feed procured from them by 7th of proceeding month: –

FORM M.C.7

Name of Distillery	Opening Balance as on previous month i.e.....	Quantity of molasses received during the month of	Quantity of molasses used for preparation of Spirit/Cattle Feed and Briquettes etc.	Quantity of molasses in balance at the end of the month.
1.	2.	3.	4.	5.

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. EXN-F(1)-2/2012(i), dated 13-03-2013 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Shimla-171002, 13rd March, 2013

No. EXN- F(1)-2/2012(i).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the East Punjab Molasses (Control) Act, 1948 as applicable to the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966, the Governor Himachal Pradesh is pleased to make the following amendments in the East Punjab Molasses (Control) (Himachal Pradesh) Rules, 1973 with immediate effect:-

AMENDMENT

In the said orders:--

Sub-rule(2) of Rule 14 of the said rules shall be substituted by the following, namely :—

“Every Distillers or manufacturers of Cattle Feed and Briquettes etc. shall furnish to the AETC/ETO I/C of the District concerned a monthly return in Form M.C.7 given below with copies thereof to the Collector (Excise) of the Zone concerned and the Excise & Taxation Commissioner, Himachal Pradesh, showing the receipt and consumption of molasses and quantity of Spirit/Cattle Feed procured from them by 7th of proceeding month:-

FORM M.C.7

Name of Distillery	Opening Balance as on previous month i.e.....	Quantity of molasses received during the month of	Quantity of molasses used for preparation of Spirit/Cattle Feed and Briquettes etc.	Quantity of molasses in balance at the end of the month.
1.	2.	3.	4.	5.

By order,
Sd/-
Principal Secretary (E&T).

ब अदालत श्री मनोज कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

Shri Tenpa Dargyal

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Tenpa Dargyal पुत्र श्री Kangdul, निवासी Upper Dharamshala, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Kunga Lhundup की जन्म दिनांक 20-11-1987 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में उक्त जन्म तिथि पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Kunga Lhundup की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 1-4-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 7-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

मनोज कुमार,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री मनोज कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री भानो राम

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री भानो राम पुत्र श्री राजू राम, निवासी भाथरी (खन्यारा), तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री शिवानी देवी की जन्म दिनांक 10-2-1994 है परन्तु ग्राम पंचायत सौकणी—दा—कोट में उक्त जन्म तिथि पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त शिवानी देवी की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 1-4-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 1-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

मनोज कुमार,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री मनोज कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती सोमिना सिंह कनेत

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती सोमिना सिंह कनेत पत्नी श्री महीपाल सिंह कनेत, निवासी दाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र नितिश कनेत की जन्म दिनांक 4-12-1990 है परन्तु ग्राम पंचायत गवली दाड़ में उक्त जन्म तिथि पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नितिश कनेत की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 1-4-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 1-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

मनोज कुमार,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री मनोज कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री भगवान दास

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री भगवान दास पुत्र स्व० श्री बैहमी राम, निवासी जुल (खन्यारा), तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पिता श्री बैहमी राम की मृत्यु दिनांक 5-3-1993 है परन्तु ग्राम पंचायत अप्पर दाड़ी में उक्त मृत्यु तिथि पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त श्री बैहमी राम की मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 1-4-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 1-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

मनोज कुमार,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री मनोज कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती इन्द्रा देवी

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी स्व० श्री रविन्द्र कुमार, निवासी कनेड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पति श्री रविन्द्र कुमार की मृत्यु दिनांक 23-10-2005 है परन्तु ग्राम पंचायत कनेड़ में उक्त मृत्यु तिथि पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त श्री रविन्द्र कुमार की मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 1-4-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 1-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

मनोज कुमार,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री मनोज कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री स्वरूप चन्द

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री स्वरूप चन्द पुत्र श्री जय राम, निवासी अन्द्राड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पत्नी श्रीमती वीना देवी की मृत्यु दिनांक 11-1-2012 है परन्तु ग्राम पंचायत टंग नरवाणा में उक्त मृत्यु तिथि पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त श्रीमती वीना देवी की मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह आकर अपना हमारी अदालत में दिनांक 1-4-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 1-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

मनोज कुमार,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री मनोज कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री सरन दास

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री सरन दास पुत्र श्री जय राम, निवासी जुल (खन्यारा), तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी माता श्रीमती तारो देवी की मृत्यु दिनांक 27-11-1977 है परन्तु ग्राम पंचायत अप्पर दाडी में उक्त मृत्यु तिथि पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त श्रीमती तारो देवी की मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 1-4-2013 को अस्सालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 1-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

मनोज कुमार,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

**In the Court of Shri Manoj Kumar, Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Dharamshala,
District Kangra, Himachal Pradesh**

1. Shri Neeraj Pradhan s/o Shri Krishan Lal, r/o Khanyara, Tehsil Dharamshala.
 2. Smt. Rashmi Thapa d/o Shri Mohinder Singh, r/o Sudher, Tehsil Dharamshala
- . . . Applicants.

Versus

1. General public
2. The Registrar of Marriages, Khanyara.

Subject.—Registration of marriage under section 8 (4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).

PUBLIC NOTICE

Whereas the above named applicants have made an application under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 17-4-2009 at Khanyara but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages, Khanyara.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage can be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, they should appear before the court of undersigned on 1-4-2013 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A. M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 1st day of March, 2013.

Seal.

MANOJ KUMAR,
*Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.*

**In the Court of Shri Manoj Kumar, Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Dharamshala,
District Kangra, Himachal Pradesh**

1. Shri Ajay Kumar s/o Shri Rajinder Kumar, r/o Sudher, Tehsil Dharamshala
 2. Smt. Poonam d/o Shri Badri Nath, r/o Mail, Tehsil Dalhousie, District Chamba
- . . Applicants.

Versus

1. General public
2. The Registrar of Marriages, Sudher

Subject.—Registration of marriage under section 8 (4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).

PUBLIC NOTICE

Whereas the above named applicants have made an application under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 6-3-2007 at Sudher but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages, Sudher.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage can be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, they should appear before the court of undersigned on 1-4-2013 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A. M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 1st day of March, 2013.

Seal.

MANOJ KUMAR,
*Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.*

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री रमेश चन्द राणा पुत्र श्री फरंगी राम, निवासी लपियाणा (डुग), डाकखाना लपियाणा, उप-तहसील हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रमेश चन्द राणा पुत्र श्री फरंगी राम, निवासी लपियाणा (डुग), डाकखाना लपियाणा, उप-तहसील हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने कार्यालय में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि उसकी लड़की कुमारी अनुबाला का जन्म दिनांक 2-8-1986 को हुआ था लेकिन ग्राम पंचायत प्रगोड के रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज नहीं है।

अतः इस इशतहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 8-4-2013 को प्रातः 10.00 बजे पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 8-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 28-3-2013

श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री बाबू राम, निवासी गांव भटोली, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. प्रत्यार्थी।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री बाबू राम, निवासी गांव भटोली, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 1-1-1990 को गांव भटोली, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कंग्रेडी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अभिलेख में पंजीकृत न करवाई जा सकी है। जन्म तिथि को पंजीकृत करने की अनुमति प्रदान करें।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 28-3-2013 को प्रातः 10.00

बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री नारायण सिंह चौहान, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, नगरोंटा बगवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

तारीख दायरा : 28-2-2013

तारीख पेशी : 28-3-2013

श्री कश्मीर सिंह सुपुत्र श्री रोशन लाल, गांव ढडखर, डाकघर संदू ब्रगां, तहसील नगरोंटा बगवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

दरखास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

चूंकि श्री कश्मीर सिंह सुपुत्र श्री रोशन लाल ने इस अदालत हजा में दरखास्त गुजारी है कि उसके पुत्र का जन्म 12-10-2004 को गांव ढडखर, डाकघर संदू ब्रगां, तहसील नगरोंटा बगवां, जिला कांगड़ा में हुआ है लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में जन्म का पंजीकरण नहीं हुआ है। प्रार्थना है कि पंजीकरण किया जावे। इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने मूल दरखास्त के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र संख्या HFW/KGR/ST(B&D)/09-115 दिनांक 27-2-2013 संलग्न किया है व ग्राम पंचायत जलोट, तहसील नगरोंटा बगवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र एवं दो गवाहान क्रमशः श्री शेर सिंह पुत्र श्री कुलदीप सिंह, निवासी गांव ढडखर, डाकघर संदू ब्रगां, तहसील नगरोंटा बगवां एवं श्रीमती सुमना देवी पत्नी श्री प्रकाश चन्द, निवासी गांव ढडखर, डाकघर संदू ब्रगां, तहसील नगरोंटा बगवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के शपथ-पत्र पुष्टि हेतु संलग्न किए हैं।

अतः इस इशतहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को विकास ठाकुर पुत्र श्री कश्मीर सिंह सुपुत्र श्री रोशन लाल, गांव ढडखर, डाकघर संदू ब्रगां, तहसील नगरोंटा बगवां, जिला कांगड़ा जिसका जन्म 12-10-2004 को हुआ है, के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह मिति 28-3-2013 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर आकर अपना उजर प्रस्तुत कर सकता है। दीगर कोई उजर काबले समायत न होगा व दरखास्त स्वीकार कर दी जाएगी।

आज दिनांक 28-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

नारायण सिंह चौहान,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नगरोंटा बगवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 6/2013

तारीख पेशी : 10-4-2013

शीर्षक :

श्री योग राज पुत्र श्री धर्म चन्द, निवासी मुहाल चम्बी, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

श्री योग राज पुत्र श्री धर्म चन्द, निवासी मुहाल चम्बी, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने सशपथ प्रार्थना-पत्र इस अदालत में पेश किया है कि उसके स्व० पिता श्री धर्म चन्द का नाम ग्राम पंचायत रझूं के अभिलेख में श्री धर्म चन्द पुत्र असताज दर्ज है जबकि राजस्व रिकॉर्ड के मुहाल चम्बी, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा में रेहला पुत्र श्री असताज दर्शाया गया है जो कि गलत है। अतः मेरे पिता का नाम राजस्व अभिलेख में दुरुस्त किया जाये।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 10-4-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड मुहाल चम्बी, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा में रेहला पुत्र श्री असताज के बजाए रेहला उपनाम धर्म चन्द पुत्र श्री असताज दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

लेख राम धीमान,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री लेख राम धीमान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 23/2011

तारीख पेशी : 8-4-2013

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

शीर्षक :

श्री विधि सिंह पुत्र, 2. सन्धी देवी पुत्री, 3. फूलां देवी पत्नी श्री तुलसी, निवासी वलोटा खास, मौजा वलोटा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . सायलान।

बनाम

स्वाति पुत्री, 2. राज कुमारी पत्नी श्री सुभाष चन्द, 3. जगदीश चन्द, 4. ईश्वर दास, 5. छांगा राम, 6. मिलाप चन्द पुत्र, 7. गोरख उपनाम गोसुख, 8. चंचला देवी पुत्री श्री वासी राम, 10. अनिल कुमार पुत्र, 11. विजय कुमार, 12. विनोद कुमार पुत्रान श्री प्रशोतम दास, 13. वीरवल, 14. प्यार चन्द पुत्र श्री प्रभू, 15. अश्वनी कुमार पुत्र, 16. अरुण कुमार पुत्र, 17. रेखा देवी पत्नी श्री शशी कुमार, 18. प्रवीण कुमार पुत्र,

19. कुशला देवी पुत्री, 20. मीरा देवी पुत्री श्री ज्ञान चन्द, 21. विमला देवी पत्नी श्री ज्ञान चन्द, 22. तरलोक चन्द पुत्र श्री भगत राम, सभी निवासी मुहाल वलोटा खास, मौजा वलोटा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश प्रतिवादीगण।

मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123 हि० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं० 25, खतौनी नं० 32 ता 39, खसरा कित्ता 79, रकबा तादादी 1-44-487 है० स्थित मुहाल वलोटा खास, मौजा वलोटा, उप तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, जमाबन्दी वर्ष 2007-08.

उपरोक्त प्रतिवादीगणों को समन जारी किए गए परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अदालत हजा को विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है।

अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 8-4-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 4-3-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

लेख राम धीमान,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं० 11/NT/13/ना० तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी।

श्री हुक्म सिंह

बनाम

आम जनता व अन्य

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री हुक्म सिंह पुत्र श्री तुलसी राम, निवासी झियोल, मौजा झियोल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र विकास सिंह की जन्म तिथि 30-7-1981 है परन्तु ग्राम पंचायत झियोल में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त की जन्म तिथि पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 12-4-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 8-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

कर्म चन्द,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

**In the Court of Shri Manoj Kumar, Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Dharamshala,
District Kangra, Himachal Pradesh**

1. Shri Pawan Katoch s/o Shri Kulbir Chand Katoch, r/o House No. B-10, KCC Colony, Jhikli Baral.
2. Smt. Surekha Katoch d/o Shri Chatter Singh, r/o Haweli, Dina Nagar, Distt. Gurdaspur
.. Applicants.

Versus

1. General Public, 2. The Registrar of Marriages, Baral.

Subject.—Registration of marriage under section 8 (4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).

PUBLIC NOTICE :

Whereas the above named applicants have made an application under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 1-4-2009 at Jhikli Baral but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages, Baral.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage may be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, they should appear before the court of undersigned on 1-4-2013 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A. M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on 4-2-2013.

Seal.

MANOJ KUMAR,
*Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.*

**In the Court of Shri Manoj Kumar, Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Dharamshala,
District Kangra, Himachal Pradesh**

Case No. 2/2013/Teh.

1. Shri Anil Gurung s/o Shri Bikram Gurung, r/o Ram Nagar
2. Smt. Vinita Gurung d/o Shri Budh Singh Gurung, r/o Dari
.. Applicants.

Versus

1. General Public, 2. The Registrar of Marriages, Mant.

Subject.—Registration of marriage under section 8 (4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).

PUBLIC NOTICE :

Whereas the above named applicants have made an application under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 19-1-1995 at Ram Nagar but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages, Mant.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage may be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, they should appear before the court of undersigned on 2-4-2013 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A. M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on 2-1-2013.

Seal.

MANOJ KUMAR,
Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.